कटिहार बिहार में स्थित पटसन मिल

1581 श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटिहार, बिहार में स्थित पटसन मिल को चालू करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) मिल को अब तक चालू न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मिल के कब तक चालू होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) : बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी एस एफ सी), जिसने कटिहार जूट मिल की परिसम्पदायों का अधिग्रहण किया है ; मुख्य रूप से उसका पुनरूद्धार करने के लिए उत्तरदायी है। कटिहार जूट मिल का पुनरूद्धार करने के पैकेज में सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा पुनरूद्धार पैकेज में उनसे अपेक्षित राहत दिया गया तथा त्याग के लिए सहमति प्राप्त करना जरूरी है।

सूती धागे का उत्पाद और आवश्यकता

1582. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम है,

(ख) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग को समूचे वर्ष कार्यरत रखने के लिए 450 मिलियन टन सूती धागे की आवश्यकता होती है,

(ग) क्या यह सच है कि मोटे तौर पर किए गए अनुमान के अनुसार इस समय केवल 300 मिलियन टन धागा उपलब्ध है,

(घ) क्या यह सच है कि देश में धागे का उत्पादन करने वाले मिलों को निर्देश दिए गए हैं कि हथकरघा उद्योग में जो सूती धागा इस्तेमाल किया जा रहा है उसके 50 प्रतिशत का उत्पादन करें,

(ङ) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सूती धागे का उत्पादन करने वाले मिल अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, और

(च) यदि हां, तो देश में हथकरघा उद्योग की आवश्यकता अनुसार सूत का उत्पादन करने के लिए सरकार कोई कारगर योजना तैयार करने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अशोक गहलोत :

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) हैंक यार्न दायित्व आदेश में प्रत्येक सूत उत्पादक को अपने कुल विक्रेय सूत का कम से कम 50 प्रतिशत सूत हैंक के रूप में पैक करना होता है जिसे सामान्यतः हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) केन्द्र सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के हितों को देखते हुए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पहले से ही हिदायतें दे दी है कि वह 40 और उससे कम काउन्ट के धागे के अधिक उत्पादन करें। सरकार ने विभिन्न राज्यों में नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों की क्षमता में विस्तार/उनके आधुनिकीकरण के लिए वित्त सहायता को एक योजना तैयार की है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में फालतू कर्मचारी

1583 डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनर्गठन संबंधी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1992 के "आब्जर्वर" में "1800 एन० टी० सी० वर्कर्स में बी० आवलेस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या निगम में कार्यरत फालतू कर्मचारियों की संख्या के बारे में पता लगा लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों में कुशल/अकुशल तथा प्रबन्धकीय कार्य में संलग्न कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ,

(ङ) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है, और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार ने एन० टी० सी० की मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिए फालतू श्रमिक बल का सुध्यवस्थीकरण इस नीति के मुख्य अंग हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश क्रमिक रूप से रुग्ण ऐसी मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों, और कामगारों को भी की जायेगी जिनके अक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा जिन्हें बन्द करना पड़ सकता है अथवा अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निकटस्थ एककों के साथ समामेलित किया जा सकता है। ऐसी आशा है कि 549 अधिकारी, 6567 कर्मचारी और 72,866 कामगार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठायेंगे।

(ङ) और (च) सर्वांगीण सुधार की नीति के अंतर्गत एन० टी० सी० के सुव्यवस्थीकृत कामगारों के पुनः नियोजन और पुनः प्रशिक्षण के लिए पुनर्वासन निधि योजना में 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। विद्युतकरघा/रीलिंग एककों की स्थापना के लिए ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए योजनाएं, पहले से ही तैयार कर ली गई हैं।

Policy Package for Revival of Jute Industry

1584. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a High Powered Committee has recommended a comprehensive policy package for the revival of jute industry;

(b) if so, what are the salient features thereof; and

(c) by when the same is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The thrust of the recommendations of the High Powered Committee is that the future of the jute sector lies in the recognition of the full potential of Jute as a fibre in diversified end applications. Technical advances and price factors render it impossible for the jute economy to sustain its existence on the production of packaging materials alone. It is, therefore, imperative for the jute sector to undertake restructuring in the interests of the jute growing farmers, mill workers and others associated with this fibre. Such diversification would help increase value realisation to the jute industry through production of intermediate raw materials like yarn and fabrics which would be utilised by the decentralised sectors for production of variegated products for diversified applications that would help generate employment. This would lead the renewed demand for jute fibre that would help farmers to realise more remunerative prices for their produce. The